भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1041
(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए)

1041. श्री विवेक गुप्ता :
क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के **प्रावधान** की ग्रामीण विकास योजना कार्यान्वित **की** जा रही है;

(ख) यदि हां, तो **इस** योजना के अंतर्गत शामिल किए गए गांवों की संख्या क्या है और इस प्रयोजनार्थ 2012-13 के दौरान कितना बजट आबंटन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन ' आदित्य')

(क) : इस समय पश्चिम बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पुरा) योजना के तहत कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) : सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) फ्रेमवर्क के तहत चलाई जा रही पुरा प्रायोगिक चरण में है और इसके तहत निजी क्षेत्र के भागीदार को संबंधित क्षेत्र की अपनी जानकारी या बुनियादी स्तर पर काम करने के पिछले अनुभव के आधार पर पुरा परियोजना शुरू करने के लिए ग्राम पंचायतों का निर्धारण एवं चयन करने की छूट दी जाती है । निजी क्षेत्र के किसी भी भागीदार ने पहली 9 प्रायोगिक परियोजनाओं के तहत कोई भी परियोजना चलाने के लिए पश्चिम बंगाल का चयन नहीं किया है ।

****